देहरादून,पौड़ी-गढ़वाल व अल्मोड़ा से प्रकाशित | www.page3news.in | नगर संस्करण वर्ष 15 अंक: 177 पृष्ठ : 8 मूल्य: एक रूपए

विचार-प्रवाह...
बिलावल की पहल

पेज थ्री

देहरादून, बृहस्पतिवार, 15 अक्तूबर 2020

PAGE 3 PUBLICATION | मौसम अधिकतम 31.0° न्यूनतम 21.0° | 37244.59

2 पाकिस्तान में आटे की भारी किल्लत | 7 धोनी ने बनाया अंपायर पर दबाव?

संक्षिप्त समाचार

पंजाब की कैबिनेट ने राज्य में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण को दी मंजूरी

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)
चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित पंजाब कैबिनेट मीटिंग में महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। पंजाब सरकार ने महिला सशक्तीकरण की दिशा में अहम फैसला लेते हुए सरकारी नौकरियों में 33 फीसदी महिला आरक्षण को मंजूरी दे दी। पंजाब सीएम ऑफिस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, मंत्रिपरिषद ने पंजाब सिविल सर्विसेज की सीधी भर्ती प्रक्रिया में महिलाओं के आरक्षण को मंजूरी दे दी।

आर्मी चीफ नरवणे को देगा नेपाली सेना के जनरल का मानद दर्जा

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) नई दिल्ली। इंडियन आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को अगले महीने नेपाली सेना के मानद जनरल का दर्जा मिलने जा रहा है। जनरल नरवणे अगले महीने नेपाल की यात्रा पर जाने वाले हैं, जिस दौरान पड़ोसी देश उन्हें इस सम्मान से नवाजेगा। नेपाली सेना के प्रवक्ता ने बताया कि जनरल नरवणे इस साल नवंबर में नेपाल का दौरा करने वाले हैं। नेपाली सेना के प्रवक्ता ने बुधवार को एक बयान जारी कर कहा, भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे इस साल नवंबर में नेपाल का दौरा करेंगे।

ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर अभिभावकों का हो रहा शोषण

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)
देहरादून। राष्ट्रीय आदर्श पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड में ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर अभिभावकों का शोषण किये जाने के विरोध में जिलाधिकारी कार्यालय में प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित कर इस दिशा में उचित कार्यवाही किये जाने की मांग की है। यहां पार्टी के कार्यकर्ता अध्यक्ष एम एस कटारिया के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और ऑनलाइन पढाई के नाम पर अभिभावकों का शोषण किये जाने के विरोध में प्रदर्शन किया।

एक नवंबर से खोले जाएंगे स्कूल

कैबिनेट की बैठक 18 प्रस्ताव आये और 17 प्रस्ताव पर मंजूरी

संवाददाता
देहरादून। उत्तराखंड में स्कूल एक नवंबर से खोले जाएंगे। पहले चरण में सिर्फ 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए ही स्कूल खुलेंगे। स्कूलों के खुलने से पहले इन्हें पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाएगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया। बैठक खत्म होने के बाद कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने विस्ता से जानकारी दी। आपको बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण के चलते लंबे समय से स्कूल बंद हैं। वहीं, बैठक में आबकारी विभाग में ट्रेक एंड ट्रेस प्रणाली लागू करने को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली है।

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में सचिवालय के वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। बैठक में त्रिवेंद्र कैबिनेट ने स्कूलों को खोलने को लेकर बड़ा फैसला लिया। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के साथ ही अभिभावकों, शिक्षण संस्थानों, शिक्षकों और जिलाधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर पर इसको लेकर विचार किया गया।

अब नहीं होगी एक दिन के वेतन की कटौती

दरअसल, लंबे समय से कोरोना वायरस संक्रमण के चलते किए लॉकडाउन में कई तरह की पाबंदियां लगाई गईं। स्कूलों को भी बंद कर दिया गया था, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई। हालांकि, पढ़ाई का ज्यादा नुकसान न हो इसको लेकर स्कूलों की ओर से ऑनलाइन क्लासेज दी जाने लगी, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों के कई हिस्सों में बच्चे ऑनलाइन शिक्षा से वंचित थे।

अनलॉक में एक-एक कर पाबंदियां हटनी शुरू हुई। अनलॉक-एक से लेकर अनलॉक-पांच में काफी हद तक व्यवस्थाएं पटरी पर आनी शुरू हुई। अब उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में एक नवंबर से स्कूलों को खोलने का फैसला लिया गया है। हालांकि, अभी सिर्फ इंटर और हाईस्कूल के बच्चों के लिए ही स्कूल खोला जाएगा।

उत्तराखंड नागरिक सुरक्षा चयन नियमावली में संशोधन

शासकीय प्रवक्ता व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कहा है कि कैबिनेट की बैठक 18 प्रस्ताव आये और 17 प्रस्ताव पर मंजूरी दी गई है ओर एक प्रस्ताव के लिए कमेटी बनाई गई है। उन्होंने कहा कि उद्योग विभाग की सेवा नियमावली में संशोधन किया गया है ओर उत्तराखंड पुलिस और मोहरीर संशोधन नियमावली संशोधन 2020 में संशोधन किया गया।

स्कूल खोलने पर विपक्ष ने उठाए सवाल

दसवीं और बारहवीं कक्षा के लिए स्कूल खोलने का कांग्रेस ने विरोध किया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि सरकार का स्कूल खोलने का निर्णय ठीक नहीं है। कोरोना काल में पर्याप्त इंतजाम ना होने के दौरान स्कूल खोलना छात्र-छात्राओं के स्वास्थ्य से खिलवाड़ हो सकता है।

राज्य कर्मचारियों को राहत

सीएम, मंत्री, विधायक, आईएएस, आईपीएस और आईऑफएस अधिकारियों को छोड़, बाकी कर्मचारियों की अब कटौती नहीं की जाएगी। राजकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयो को अनुदान दिए जाने को लेकर कैबिनेट में चर्चा किया गया। जिस पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड नागरिक सुरक्षा अधीनस्थ चयन आयोग नियमावली में संशोधन किया गया है और राजकीय महाविद्यालय में छात्र निधि का समुचित उपयोग और प्रबंधन के लिए नियमावाली बनाई गयी है और पीरुल नीति के तहत, पीरुल इकट्ठा करने पर पहले एक रुपए प्रति किलो का दाम तय है जिसे बढ़ाकर अब 2 रुपये किया गया है।

पुलिस विभाग को चालान की संख्या में वृद्धि करने के निर्देश

परिवहन मंत्री ने राज्य सड़क सुरक्षा परिषद विषय के संबंध में बैठक की

संवाददाता
देहरादून। प्रदेश के परिवहन मंत्री यशपाल आर्य ने विधान सभा कक्ष में राज्य सड़क सुरक्षा परिषद विषय के संबंध में बैठक की। उन्होने बैठक में वर्ष 2022 तक दुर्घटना की संख्या आधी करने का लक्ष्य निर्धारण करने हेतु निर्देश दिये। आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि प्रवर्तन कार्य पर जोर दिया जाय, लाईसेन्स निलम्बित करने के साथ निरस्तीकरण की भी कार्यवाही की जाय। पुलिस विभाग को चालान की संख्या में वृद्धि करने के निर्देश दिये गये। इसके लिए ऑन लाईन ट्रैकिंग व्यवस्था और ई-चालान सिस्टम को अपग्रेड किया जाय। इसके अलावा प्रवर्तन कार्य के सुदृढीकरण हेतु हाइवे पेट्रोल यूनिट के गठन की कार्यवाही तेज कर दी जाय।

बैठक में कहा गया कि ट्रैफिक नियमों का पालन की समीक्षा की जाय, चिन्हित दुर्घटना सम्भावित स्थलों का चिन्हिकरण एवं सुघारीकरण के लिए स्थलों पर क्रश बैरियर का निर्माण और रोड सेफ्टी आडिट कराया जाय।

मंत्री यशपाल आर्य ने कहा, जनपद स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की निरन्तर बैठक ली जाय। जनपद स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की वर्ष में दो बैठक होना अनिवार्य है। इस सम्बन्ध में देहरादून और उधमसिंह नगर में निर्धारित बैठक पूर्ण करने के निर्देश दिये गये है। दुर्घटना रोकने के लिए जगरूकता अभियान बढाने के निर्देश दिये गये इस सम्बन्ध में पुलिस प्रशासन, स्वस्थ्य, परिवहन विभाग के समन्वय से कार्यवाही की जाय। ट्रैफिक अवेयरनेश सेन्टर खोलने के लिए भूमि चयन की कार्यवाही एक माह के भीतर कर ली जाय।

इस अवसर पर परिवहन सचिव, शैलेश बगोली, सचिव पीडब्लूडी, आर के सुधांशु, सचिव, आयुक्त गढ़वाल मंडल रविनाथ रामन, इत्यादि अधिकारी उपस्थित थे।

शिक्षा नीति के स्टार्स प्रोजेक्ट को कैबिनेट की मंजूरी

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के तहत नई योजना के तौर पर स्टार्स प्रोजेक्ट को शुरू किया जाएगा। छह राज्य इसके दायरे में आएंगे। इस परियोजना पर 5718 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई बैठक में इस परियोजना को मंजूरी दे दी गई। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और नरेंद्र सिंह तोमर बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी।

जावड़ेकर ने बताया कि नई शिक्षा नीति को अमली जामा पहनाने से जुड़े स्टार्स प्रोजेक्ट को आज मंजूरी दे दी गई। इस परियोजना के लिए विश्व बैंक की ओर से 50 करोड़ डालर की वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह प्रोजेक्ट केंद्र द्वारा प्रायोजित नई योजना के तहत शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा लागू किया जाएगा। फिलहाल छह राज्यों हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल और ओड़िशा को इस परियोजना के दायरे में लाया जाएगा। इसके तहत राज्यों को शिक्षा ढांचे में सुधार के लिए विकास, क्रियान्वयन और मूल्यांकन आदि क्षेत्रों में सहायता की जाएगी।

फैसले

■जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए विशेष पैकेज पर भी मुहर

जावड़ेकर ने बताया कि कैबिनेट ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान श्दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत 529 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज को भी मंजूरी दी है। जावड़ेकर ने कहा कि देश के सभी ग्रामीण इलाकों में दीन दयाल अंत्योदय राष्ट्रीय आजीविका मिशन योजना चलती है। ग्रामीण कश्मीर, लद्दाख और जम्मू में रहने वाले 2/3 लोग इस योजना में शामिल होंगे।

Are you Planning to make a Website or already have ?
If yes, then we are here to serve you

What we do

Website Development
All type of Websites E-Commerce, Hotel Booking, Travel, Bus Ticket Booking, News Portal, Blogs, or as per client requirement.

Promotion & Branding
1. Website Promotion & Branding in any country (200+ Countries)
2. Social Media
3. Bulk SMS

Search Engine Optimisation
A-2-Z Work to make a Website Search Engine Friendly.
You tell us, we do it.

Contact:
Gadoli Media Ventures
Shivam Market, 2nd Floor, Darshan Lal Chowk, Dehra Dun. I Mob: 9319700701, 7579011930
E-Mail: contact@gadoli.in

भारत में कोरोना वैक्सीन को लेकर एक अच्छी खबर

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)
नई दिल्ली। भारत में कोरोना वैक्सीन को लेकर एक अच्छी खबर आई है। भारत में रूसी कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी के ट्रायल को पिछले दिनों नामंजूर कर दिया गया था। इसके बाद भारतीय दवा निर्माता डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज ने फिर से ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को एक संशोधित आवेदन प्रस्तुत किया है, जो भारत में रूसी कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक वी के दूसरे और तीसरे चरण के क्लीनिकल ट्रायल को संचालित करने के लिए एक सरकारी अधिकारी से अनुमोदन की मांग कर रहा है।

कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी के ट्रायल की कवायद तेज

हाल ही में, डीसीजीआई के विशेषज्ञ पैनल ने सिफारिश की थी कि डॉ रेड्डीज लैब वैक्सीन के ट्रायल को मंजूरी दिलाने के लिए नए सिरे से संशोधित आवेदन प्रस्तुत करे। पिछले हफ्ते, विशेषज्ञ समिति (एसईसी) ने डॉ रेड्डी लैब द्वारा प्रस्तुत पिछले आवेदन का गहन मूल्यांकन किया। इसके बाद, एसईसी ने फार्मा कंपनी को अधिक जानकारी के साथ संशोधित प्रोटोकॉल के साथ आवेदन करने का निर्देश दिया था।